

प्राप्तक

श्री दया राम,
अपर सचिव,
उत्तरावल।

गोदाम

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

आंध्रोगित विकास विभाग
दिनांक 30 अप्रैल-2001

देहरादून

विषय: उत्तरांचल राज्य खनिज नीति-2001

महादेव

उत्तरांचल राज्य , विभिन्न प्रकार के उपलब्ध खनिजों का दोहन आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने, पर्यावरण का संरक्षण एवं खनिज क्षेत्रों की पुनर्स्थापना करने, खनिज घण्टारों का अधुनिक तकनीक द्वारा विस्तृत अन्वेषण का कार्य करने तथा खनिजों के दोहन एवं चुग्नन के कार्यों में माफियाओं के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु शामिल द्वारा उत्तरांचल राज्य खनिज नीति-2001 प्रख्यापित की गयी है। अतः उत्तरांचल राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में बांधित जावशक्तियों की पूर्ति एवं मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णयों को चरणबद्ध व समयबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

मूल्य लिनिज़:

मुख्य खनिजों का विकास एवं विनियम खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम-1957 की धारों एवं खनिज परिहार नियमावली-1960 के प्रविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। उक्त अधिनियम व नियमावली भारत-सरकार द्वारा प्रदृष्ट की गई है। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुमूची के भाग-ए एवं बी में स्पेशिफाइड मिनरल्स अंकित है, जिसको रिकॉर्डइसेम परमिट/पी0एल0/एम0एल0 पर स्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा भारत-सरकार में भनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। अन्य मुख्य खनिज, जो उक्त अधिनियम के द्वितीय अनुमूची में अंकित है, को रिकॉर्डइसेम/पी0एल0/एम0एल0 पर स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत-सरकार से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रदेश के अन्तर्गत सतही एवं भूर्गमय में पाये जाने वाले खनिज प्रदेश की स्पष्टि होती है तथा सतही अधिकार प्रदेश में निहित है, इसलिए खनिज देश रायल्टी प्रदेश सरकार द्वारा ही वसूल की जायेगी।

मुख्य खनिजों के सूनियोजित विकास के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. शासन द्वारा सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया जायेगा। कार्यकारी दल द्वारा मुख्य खनिजों के खनन में अपनायी जा रही तकनीक, उनका पर्यावरण पर प्रभाव तथा खनन से सम्बन्धित प्रचलित कार्यप्रणाली को व्यवहारिक बनाने के सम्बन्ध में उपाय एवं सुझाव तैयार कराये जायेंगे। कार्यकारी दल के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत-सरकार को मुख्य खनिजों के खनन से सम्बन्धित खन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 के सम्बन्ध में सुझाव देने का भी होंगा।
 2. मुख्य खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्र के ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिनके पास यह कार्य करने हेतु पर्याप्त पूँजी एवं आधिकारिक तकनीक उपलब्ध हो।

3. खनिज युक्त क्षेत्रों में अवस्थापना की सुविधा उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार द्वारा खनिज स्टेट स्थापित किये जायेगे।
4. खनिज विकास एवं अन्वेषण कार्यों के लिए खनिज विकास निधि की स्थापना की जायेगी। मुख्य खनिजों के खनन से प्राप्त रायलटी का 5 प्रतिशत इस निधि में जमा किया जायेगा।
5. हेतु खनिज निदेशालय ये एकल मेंज व्यवस्था (सिंगल विंडो सिस्टम) की स्थापना की जायेगी।
6. निम्न श्रेणी, सौमांत श्रेणी, खनन मलवा एवं खनिज आधारित उद्योगों के सह-उत्पादों को उपयोग में लाने का यथा साध्यव प्रयास किया जायेगा।

उप-खनिजः

वर्तमान में बन क्षेत्रों के बाहर उपखनिजों का खनन/चुगान का कार्य मुख्य रूप से निजी पटाधारकों के द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसा अनुभव किया गया है कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत धीरे-धीरे खनन् एवं चुगान आदि कार्यों में एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। इस प्रक्रिया पर अंकुश लगाने के लिए तथा उपखनिजों का दोहन आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा करने हेतु उपखनिजोंके खनन् व चुगान का कार्य शासकीय नियमों द्वारा ही कराया जाये।

बन क्षेत्रों में बनों के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए खनिजों के खनन् एवं चुगान का कार्य उत्तरांचल बन निगम के पाठ्यम से कराया जायेगा। निगम द्वारा इह कार्य स्वर्य किया जायेगा तथा किसी को सुल्लेट

बन क्षेत्र के बाहर सिविल क्षेत्रों में उप-खनिजों के खनन् एवं चुगान का कार्य सरकारी निगमों/सरकारी विभागों/कानूनी निगमों द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु इन संस्थाओं को आयोजनेतर पक्ष में कोड भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी तथा उनके द्वारा कोई अतिरिक्त दायित्व भी सृजित नहीं किया जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में सरकारी निगमों एवं शासकीय विभागों द्वारा उपखनिज के खनन्/चुगान के कार्यों को नियादित करने में असमर्थता, व्यक्त की जाती है या वे शासन द्वारा इस कार्य में असम पाये जाते हैं, तो इन परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप यह कार्य निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को पटटे के आधार पर नियन्त्रित रूप से किया जायेगा:-

1. सर्वप्रथम छोटे आकार के लादस बनाये जायेंगे।
2. किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक लाद का पटटा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. पटटा हेतु जनपद के मूल निकासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. यह मुनिशिचत किया जायेगा कि पटटे हेतु आवेदन करने वाला व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का न हो। निवास एवं चरित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला प्रशासन से प्राप्त किया जायेगा।

मैदानी क्षेत्र, विकासनगर, देहरादून, डॉइन्काला, झाविकेश, हल्हानी, उष्मसिंहनगर, हरिद्वार को छोड़कर, शेष पर्वतीय क्षेत्रों में, जिलाधिकारियों को निम्न अधिकार दिये जायें:-

1. निजी भवनों के निर्धारण हेतु आपश्यकतानुसार स्थानीय लोगों को निर्धारित दर पर निःशुल्क अधिकतम् 150 घनमीटर तक बौल्डर, बबरी, रेत आदि का परमिट दिया जायेगा।

उप खनिजों की रायलटी के सम्बन्ध में सम्प्रति सामान्य अंकलन के आधार पर वर्तमान में प्रचलित दरों में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी। रायलटी का अंतिम रूप से निर्धारण विभिन्न बिन्दुओं पर विचारोपण तकनीकी दृष्टिकोण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से, एवं राजस्व हित को देखते हुए किया जायेगा। और तदनुसार निर्णयोपरांत शासनादेश शीघ्र ही निर्गत कर दिया जायेगा। वन विकास निगम एवं अन्य सरकारी विभाग/निगम, जो उपखनिजों के खनन के कार्य के लिए अधिकृत होंगे, वे प्राप्त राजस्व की सूचना हर माह खनिज निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। प्रश्नगत निगम/विभाग रायलटी पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

उप खनिजों के खनन से प्राप्त राजस्व का 5 प्रतिशत धनराधि को खनिज निधि में इस उद्देश्य से रखा जायेगा, जिसका उपयोग वन खनिजों के खनन क्षेत्रों में भू-भाग पुर्वस्थापना हेतु किया जायेगा।

उप खनिजों के चुगान/खनन की संक्रियायें उत्तरांचल उपखनिज (परिहार) नियमावली-2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, और कृत-कार्यवाही से समय-समय पर शासन को अवगत कराने का काष्ट करें।

भवदीय

(दया राम)

अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या 1031/आ०वि०/२००१ तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सभी सरकारी निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिजकार्य विभाग, उत्तरांचल।
3. नोडल अधिकारी/उप-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।
4. प्रधारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून/हल्ड्झानी।
5. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(दया राम)

अपर सचिव